मंगू खान एवं अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

24 फ़रवरी 2005

[के. जी. बालाकृष्णन एंड बी.एन. श्रीकृष्ण, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860-धारा 302 धारा 34 के साथ पठित, धारा 148, 302/149 और 323/149-विवाद पर दो व्यक्तियों की हत्या और दूसरे को चोट पहुंचाना-धारा 148, 302/149 और 323/149 के तहत दोषसिद्धि-उच्च अदालत ने आईपीसी की धारा 302, धारा 34 के साथ पठित और धारा 323/34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया - का औचित्य: मौके पर अपराध करने के सामान्य इरादे के गठन और शिकायतकर्ता पक्ष पर जिस तरह से हमला किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसे दर्शाने वाले साक्ष्य हालांकि, विशेष आरोपी की पहचान करना और उसे विशेष चोट पहुंचाना संभव नहीं है - इसलिए, आईपीसी की धारा 302 के साथ पढ़ी गई धारा 34 के साथ सजा उचित है - साथ ही साक्ष्यों में कोई विसंगतियां नहीं हैं - साक्ष्य अधिनियम, 1872।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136-साक्ष्य की पुनः अनुशीलन सुप्रीम कोर्ट स्कोप ऑफ-अभिनिर्धारित : जब नीचे की अदालतें आरोपों को बनाए रखने के लिए सबूतों को एक साथ स्वीकार करती हैं, तो सबूतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने मुखबिर पर हमला किया मेड़ बांधने के विवाद को लेकर पिता और भाई हथियार के साथ। पिता और उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और शिकायतकर्ता भाई घायल हो गया। शिकायतकर्ता ने दर्ज कराई एफआईआर. अपीलकर्ताओं को धारा 148, धारा 302/149 और धारा 323/149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को धारा 302 आईपीसी के साथ धारा 34 आईपीसी और धारा 323/34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसलिए, वर्तमान अपील करता है।

अपीलकर्ता-अभियुक्त ने तर्क दिया कि चूंकि सत्र न्यायालय ने किया था अपीलकर्ताओं को धारा 302 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया, उच्च न्यायालय उन्हें धारा 302 आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत दोषी नहीं ठहरा सका; यदि वे दोषी भी हों तो भी उन्हें केवल धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए, न कि धारा 302 के तहत; साक्ष्य में विसंगतियाँ; अपीलकर्ता संख्या I और 2 को लगी चोटों के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था; उच्च न्यायालय ने यह न समझकर गलती की कि नेत्र संबंधी साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ असंगत थे; और निजी बचाव का अधिकार अभियुक्तों को उनकी संपत्ति और व्यक्ति दोनों के संबंध में उपलब्ध था।अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए सबूतों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कुछ विसंगतियां हैं

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया : 1 ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से स्वीकार किया आरोप को कायम रखने के लिए सबूत, सबूतों का सूक्ष्म विश्लेषण में नहीं जा सकते. (372-डी)

हर्षदसिंह पहलवानसिंह ठाकोर बनाम गुजरात राज्य, 1976 4 एससीसी 640, संदर्भित।

2.1. इसमें कोई संदेह नहीं कि पिता और उसके पुत्र को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों, अर्थात् खोपड़ी, को गंभीर चोटें पहुंचाईं। अपीलकर्ताओं का इस तरह की चोटें पहुंचाने का सामान्य इरादा था क्योंकि वे सुबह-सुबह मैदान में हथियारों के साथ इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया गया और उनमें से दो को मौत के घाट उतार दिया गया, वह सबूतों से पता चलता है और इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष उचित हैं। सबूतों से, उस व्यक्ति को इंगित करना संभव नहीं हो सकता है जिसने प्रत्येक मृतक को घातक झटका दिया और इस तरह सभी अपीलकर्ताओं को धारा 302 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया। लेकिन जब साक्ष्य यह इंगित करता है कि तीनों अभियुक्तों ने लाठी, फ़ारसी और टंचिया से बार-बार प्रहार किया था, और किसी विशेष अभियुक्त की पहचान करना और विशेष चोट का आरोप लगाना संभव नहीं है, तो अभियुक्त को धारा 302 के तहत आरोप में दोषी ठहराया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 न्यायसंगत है। इसके अलावा, स्थिति खुली लड़ाई की नहीं थी और रिकॉर्ड पर एफ साक्ष्य

इंगित करता है कि इरादा उन व्यक्तियों पर घात लगाकर हमला करना और उन्हें मारना था, जो भूमि पर गैरकानूनी निर्माण के बारे में विरोध करने आ रहे थे। इसलिए, स्थिति धारा 302 के अंतर्गत आती है न कि धारा 304 के द्वारा। (377-जी-एच; 378-ए-सी; 379-ई)

बी.एम. दाना और अन्य। बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर (1960) एससी 289; हर्षदसिंह पहलवानसिंह ठाकोर बनाम गुजरात राज्य, (1976) 4 एससीसी 640; सुखराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर (1974) एससी 323 और पीपल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2001) 2 एससीसी 292, संदर्भित)।

2.2. यह नहीं कहा जा सकता कि हर मामले में एक असहनीय बोझ हैअभियोजन पक्ष को अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा ऐसा न करने पर अभियोजन मामले को ताला, स्टॉक और बाहर फेंक दिया जाना चाहिए बैरल। केवल इसलिए कि अपीलकर्ता-अभियुक्त व्यक्तियों को शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर छोटी-मोटी खरोंचें और चोट लगी है और अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें समझाया नहीं गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि साक्ष्य, जो अन्यथा स्वीकार्य है, संदिग्ध हो जाता है या अभियोजन विफल हो जाना चाहिए उस स्कोर पर. (374-जी; 375-एफ)

हरे कृष्ण सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1988) एससी 863,पर भरोसा।

2.3. पोस्टमार्टम जांच II.OOA.M./12 में की गई 11.7.1997 को दोपहर और रिपोर्ट बताती है कि मृत्यु "पोस्टमार्टम परीक्षा से 24 घंटे के भीतर" हुई थी। हो सकता है I0.7.1997 की दोपहर 11.00/12.00 के बाद किसी भी समय घटित हुआ। कठोर मोर्टिस का विकसित होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे मृतक की संरचना, वर्ष का मौसम, क्षेत्र का तापमान और वे परिस्थितियाँ जिनके तहत शरीर को संरक्षित किया गया है। रिकॉर्ड बताता है कि शव को मुर्दाघर से ले जाया गया था। डॉक्टर से किसी भी तरह की जिरह नहीं की गई है ताकि कोई भी भौतिक तथ्य सामने आ सके जिस पर संभावित तर्क दिया जा सके।' यदि ये परिस्थितियाँ हैं, तो पूरे शरीर में कठोर मोर्टिस की उपस्थिति अपने आप में यह मानने की गारंटी नहीं दे सकती है कि मृत्यु पिछली रात के दौरान हुई होगी। ऐसे काल्पनिक आधार पर स्वीकार्य नेत्र साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता।

(376-सी-एफ)।

2.4. अभियुक्त ने उपलब्धता के संबंध में कोई दलील नहीं दीअभियुक्तों को उनकी संपत्ति और उनके संबंध में निजी बचाव का अधिकार मुकदमे के दौरान किसी व्यक्ति ने, न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह के दौरान इसका सुझाव दिया। इसके अलावा रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि शिकायतकर्ता पक्ष के किसी भी सदस्य ने ऐसा कोई कार्य किया था जिससे आरोपी के मन में उनके व्यक्ति या उनकी संपत्ति को खतरे की उचित आशंका पैदा हो सकती थी, या कि उन्होंने आरोपी पक्ष से संपर्क किया हो। शारीरिक क्षति पहुँचाने के इरादे से, क्योंकि वे पूरी तरह से निहत्थे थे।[376-एच; 377-ए-बी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 30 2004 का.

राजस्थान उच्च के निर्णय एवं आदेश दिनांक 1.7.2003 से कोर्ट डी.बी.सीआरएल.ए. 1998 की संख्या 809।

साथ

सी.आर.एल.ए. 2004 की संख्या 31.

एस.आर. बाजवा, सुशील कुमार. जैन, हेमराज गुप्ता, एच.डी. थानवी, एस सिंघानिया, अपीलकर्ताओं के लिए प्रतिभा जैन और अजाऊ चौधरी।

प्रतिवादी की ओर से कुमार कार्ति कैट और सुश्री संध्या गोस्वामी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

श्रीकृष्ण, न्यायमूर्ति

अपीलकर्ताओं को धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया था, ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 और धारा 323/149 के तहत उन्हें सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील में असफल होने के बाद, अपीलकर्ता विशेष अनुमति के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष हैं।

तथ्य:

साहब खान, पीडब्लू 3, ने 11.7.1997 को एक लिखित रिपोर्ट (उदा. पी 6) बनाई प्रातः 9:00 बजे, पुलिस थाना सदर, अलवर। उनके अनुसार, उस दिन सुबह 7:00 से 7:30 बजे के बीच, वह और उनके पिता, धंधड़ और उनके भाई, लसब, अपने खेत में गए थे। मंगू खान, अपीलकर्ता नंबर 1, सिरदार खान, अपीलकर्ता नंबर 2, सूबेदार खान, अपीलकर्ता नंबर 3, (दीन मोहम्मद और जमील खान, जब से बरी हुए हैं), जिनकी एक बांध के निर्माण के कारण उनसे दुश्मनी थी, थे विधिवत लाठी, फारसी, टंचिया और कट्टा से लैस होकर मेड़ पर बैठे। जैसे ही सूचक, उसके पिता और भाई पहुंचे, उपरोक्त सभी लोगों ने उन पर फरसी, लाठी और टंचिया से हमला कर दिया. नतीजतन, धांधड़ और उसका भाई इसब नीचे गिर गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हमले के परिणामस्वरूप उन्हें कुछ चोटें भी आईं। पुलिस थाना सदर अलवर ने धारा 147, 148, 149, 307, 447 व 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच के परिणामस्वरूप, पांच आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। उनमें मंगू खान, अपीलकर्ता नंबर I, सिरदार खान, अपीलकर्ता नंबर 2, सूबेदार खान, अपीलकर्ता नंबर 3, दीन मोहम्मद शामिल थे। और जमील खान. विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर ने उक्त आरोपी को एल.पी.सी. की धारा 148, 302/149 और 323/149 के तहत दोषी ठहराया। और उन्हें धारा 148 के तहत अपराध के लिए दो साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना, आजीवन कारावास के लिए कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ अपराध के लिए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। धारा 302/149 आईपीसी, और इसके तहत अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगाधारा 323/149 आईपीसी.

पांचों आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की. अपील पर उच्च अदालत का मानना था कि अपीलकर्ता दीन मोहम्मद के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 302/149 और 323/149 के तहत आरोप लगाए गए हैं। और जमील खान को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया और उन्हें बरी कर दिया गया। वर्तमान अपीलकर्ताओं की संख्या। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा मुझे धारा 302 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, साथ ही दो साल के

कठोर कारावास की डिफ़ॉल्ट सजा और दोषसिद्धि के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 323/34 के तहत. सजाएँ एक साथ चलने का निर्देश दिया गया।

विद्वान वकील. अपीलकर्ता ने हमें मिनट में जाने के लिए आमंत्रित किया साक्ष्यों का विवरण हमें यह समझाने के लिए कि अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने साक्ष्यों में कुछ विसंगतियों और विसंगतियों को उजागर करने का भी प्रयास किया। दो अदालतों ने आरोप को कायम रखने के लिए सबूतों को सहमति से स्वीकार कर लिया है, हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के निमंत्रण पर सबूतों के सूक्ष्म विश्लेषण में जाने से इनकार करते हैं। हम इस संबंध में ***हर्षदसिंह पहलवानसिंह ठाकोर बनाम गुजरात राज्य***[1] मामले में इस न्यायालय के आदेश को उपयोगी रूप से दोहरा सकते हैं। '

> "न्यायिक शिखर सम्मेलन, जब विवाद के विषय का पुनर्मूल्यांकन किया जाता हैगलत मूल्यांकन के परिष्कृत आधार पर भी सबूत होना जरूरी हैप्रक्रियात्मक समरूपता के कुछ आत्म-नियंत्रित नियमों के प्रति स्वयं को समर्पित करें।ट्रायल कोर्ट गवाहों की गवाही को सीधे देखता है और उनकी सत्यता का परीक्षण करता है। द. अपीलीय न्यायालय, की व्यापक शक्ति का आनंद ले रहा हैपरीक्षण, सावधानी से इसका अभ्यास करता है, संभावित त्रुटियों की तलाश करता हैरिकॉर्ड में मूल्यांकन, निरीक्षण या चूक और बेहतर बनाता हैस्थापित नियमों के आलोक में सामग्रियों की समग्रता पर निर्णयआपराधिक न्यायशास्त्र का. जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है, फोरेंसिक समीक्षा की जाती है अधिक दुर्लभ है. ऐसा प्रतिबंधक, दृष्टिकोण, सर्वोच्च है हमारी व्यवस्था को ठप्प किये बिना न्यायालय को राजी नहीं किया जा सकतान्यायपालिका, सबूतों को पढ़ने के आधार पर जाने के लिए। औरइसकी नई व्याख्या करना ताकि जो बात इसे पसंद आए उसे बरकरार रखा जा सके संभावित वैकल्पिक विचार. यदि विकृति है, न्याय का गर्भपात है,चौंका देने वाली गलत व्याख्या या स्थूलता। नियमों का गलत प्रयोग, प्रक्रियात्मक और वास्तविक, हम बिना किसी हिचकिचाहट के हस्तक्षेप करते हैं। का। पाठ्यक्रम अन्यअसाधारण परिस्थितियाँ भी हमारे समीक्षा

क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकती हैं। ये पूर्व-अवलोकन आवश्यक हो गए हैं, आमतौर पर, अपीलकर्ता, उम्मीद है कि इन न्यायिक सीमाओं के बारे में अस्पष्ट तर्क देंगे पूरे रास्ते हमारे सामने ऐसे हैं जैसे पूरे सबूत डेनोवो परीक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हों। वर्तमान मामले में ऐसी प्रक्रिया का प्रयास किया गया है और, ऊपर बताए गए कारणों से, हम यह पता लगाने के लिए गवाही को तोड़ने के इच्छुक नहीं हैं कि सबूत विश्वसनीय हैं या नहीं।"

अपील के तहत फैसले के पैराग्राफ 31 में उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया है:

"31.एल। उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम उभरे तथ्यों पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं तात्कालिक मामले को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:-

(i) मृत लसब के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में 7 कटे हुए घाव और दाहिने हाथ और दाहिनी जांघ पर 3 खरोंचें आईं।

(ii) मृतक धंधड़ के सिर पर 9 कटे हुए घाव आए शरीर के अन्य हिस्से और खोपड़ी पर चोट के दो निशान।

(iii) अपीलकर्ता मंगू को दोनों हाथों पर चार खरोंचें आईं नाक। जबकि अपीलार्थी सरदार के दाहिनी ओर चोट लगी है पैर, दाहिने कंधे पर कई खरोंच के निशान और दो खरोंचें बायां घुटना।

(iv) मुखबिर साहब खान के सिर पर चोट लगी थी,बाएं कंधे और दाहिनी कलाई पर चोट के निशान और बाएं पैर पर खरोंच।

(v) अपीलकर्ता के बीच घटना की तारीख से 0-12 दिन पहले से खेत की विभाजन दीवार को लेकर विवाद चल रहा था। मंगू और मृतक.

(vi) साइट प्लान के अनुसार मृतक का निवास स्थान (धानी)। से लगभग 300 मीटर दूर मंगू के खेत की ओर स्थित है घटना का स्थान.

(vii) लसब और धंधड़ के शव खेत में पड़े मिले मंगू का.

(viii) मुखबिर साहब खान का खेत मंगू के खेत के ठीक बगल में दक्षिण की ओर स्थित है।

(ix) जाकिर हुसैन (Pw. I), रुदार (Pw.2), शरीफ खान (Pw.4) और रियासत अली (Pw. 5) का बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। 14 जुलाई, 997 यानी घटना के करीब 3 दिन बाद. के अनुसार नरपत सिंह राठौड़, इं0. (पृ. 15) वे उसके लिए उपलब्ध नहीं थे।

(x) जिरह हेतु नरपत सिंह राठौड़, 1.0. स्वीकार किया कि अपीलकर्ता जमील के कहने पर बरामद फ़ारसी को सील कर दिया गया और अनुच्छेद एल-ए के रूप में चिह्नित किया गया। लेख पर एक पर्ची चिपकाई गई थी जिस पर उनके हस्ताक्षर थे और दिनांक जुलाई I, I, I 997 थी, लेकिन उस पर जमील के हस्ताक्षर नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि जमील को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था; 1997 और उनकी गिरफ़्तारी के बाद फ़ारसी बरामद हुई।

(xi) इसमें चूक, अलंकरण और विरोधाभास हैं साहब खान का बयान (Pw.3).

(xii) अपीलकर्ता मंगू और सिरदार खान को चोटें आईं अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया।

(xiii) मृतकों को ले जाते समय रास्ते में पुलिस चौकी गिरने के बावजूद शव मुखबिर ने पुलिस को पहली सूचना नहीं दी."

ये निष्कर्ष मोटे तौर पर सही हैं और इन्हें आधार के रूप में लिया जाना चाहिए अपील के तहत निर्णय का कोई और महत्वपूर्ण मूल्यांकन।

विवाद:

विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया पहला तर्क यह है कि मंगू खान और सिरदार खान को भी चोटें लगी थीं, जिसे अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट नहीं किया था। नतीजतन, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला संदिग्ध हो जाता है और उचित संदेह उत्पन्न करता है, जिसका लाभ वैध रूप से अभियुक्त को मिलना चाहिए। मृतक इसाब और धांधड़ को चोटें आई हैं

शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। सूचना देने वाले साहब खान के सिर के दाहिनी ओर एक घाव और दाहिनी कलाई और बाएं पैर पर क्रमशः तीन खरोंचें आई थीं। जहां तक आरोपी व्यक्तियों को लगी चोटों का सवाल है, चोट रिपोर्ट में शरीर के गैर-जी महत्वपूर्ण हिस्सों पर छोटी-मोटी खरोंचें और घाव दिखाई देते हैं, इसके अलावा, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि हर मामले में ऐसा असहनीय होता है अभियोजन पक्ष पर यह बोझ डाला जाए कि वह अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण दे, ऐसा न करने पर अभियोजन मामले को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ***हरे कृष्ण सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य***[2] इस न्यायालय ने, कई निर्णयों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद उक्त प्रस्ताव के लिए प्राधिकारियों के रूप में इसके समक्ष उद्धृत किया गया, निम्नानुसार देखा गया: (ए पैराग्राफ 18 के अनुसार)

> "अभियुक्त का अपराध सिद्ध करने का भार निःसंदेह उस पर है अभियोग पक्ष। आरोपी बचाव में कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं है। अभियोजन पक्ष को सभी से परे आरोपी का अपराध साबित करना होगा उचित संदेह. यदि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया जाता है कि उनका अपराध सिद्ध है किसी भी उचित संदेह से परे आरोपी, दायित्व का प्रश्न अभियोजन पक्ष को अभियुक्तों को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा उत्पन्न नहीं होगा. जब अभियोजन पक्ष एक निश्चित मामले के साथ आता हैअपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है और इसका मामला साबित होता है, किसी भी उचित संदेह से परे, यह शायद ही आवश्यक हो जाता है अभियोजन पक्ष को फिर से यह बताना होगा कि चोटें कैसे और किन परिस्थितियों में लगीं अभियुक्त के शरीर पर प्रहार किया गया है।"

फिर, इस प्रकार अनुच्छेद 20 में:

> "इस न्यायालय के सभी निर्णय जिनका उल्लेख किया गया है और ऊपर चर्चा की गई है, दिखाएँ कि जब न्यायालय ने इस पर विश्वास किया है न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को विश्वसनीय और विश्वसनीय बतायाजैसा कि अभि योजन पक्ष ने कहा था, आरोपी की दलील को खारिज कर दिया इसमें अभियुक्तों को लगी चोटों के

बारे में बताने में असफल रहे घटना, अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और अभियुक्त को बरी कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह कानून या अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि जब भी आरोपी को उसी घटना में चोट लगती है, तो अभियोजन पक्ष को चोटों की व्याख्या करनी होगी, जिसका अर्थ यह होगा कि अभियोजन पक्ष ने सच्चाई को दबा दिया है और घटना की उत्पत्ति और उत्पत्ति को भी दबा दिया है।

"इस आधिकारिक घोषणा के सामने, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ताओं, मंगू खान और सिरदार खान के शरीर पर कुछ खरोंचें और मामूली कटे हुए घाव थे, जो साक्ष्य अन्यथा स्वीकार्य हैं, वे संदिग्ध हो जाते हैं या कि अभियोजन उस स्कोर पर विफल होना चाहिए।

विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने स्थूल रूप से इस बात की सराहना न करने में गलती हुई कि रिकॉर्ड पर नेत्र संबंधी साक्ष्य पूरी तरह से मौजूद थे असंगत बुद्धि और चिकित्सीय साक्ष्य के आलोक में समझ से परे। विशेष रूप से, विद्वान वकील ने हमारा ध्यान पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओर आकर्षित कियादोनों मामले. मृतक इसाब के मामले में, दिनांक 11.7.1997 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि शरीर की जांच 11.1.97 को दोपहर 12.00 बजे की गई थी और प्रमाणित किया गया था कि मृत्यु "पीएम परीक्षा से 24 घंटे पहले" हुई थी। मृत्यु का कारण सिर और खोपड़ी पर गंभीर चोट लगना प्रतीत होता है, जिसके परिणामस्वरूप घाव मेनिन्जेस में गहरे चले गए, मस्तिष्क का पदार्थ हड्डियों और खोपड़ी के माध्यम से बाहर आ गया। मृतक दंडहाद के मामले में, दिनांक 11.7.1997 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने प्रमाणित किया कि उसके शरीर की जांच सुबह 11.00 बजे की गई थी और मृत्यु "पीएम परीक्षा से 24 घंटे पहले" हुई थी। दोनों मामलों में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में "पूरे शरीर पर कठोर मोर्टिस मौजूद" होने का संकेत मिला। इन दो दस्तावेजों के आधार पर, विद्वान वकील ने एक मामला बनाने की कोशिश की कि अभियोजन पक्ष की कहानी अविश्वसनीय थी, कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिछली रात खुले मैदान में अपराध किया गया था और आरोपी पर मामला झूठा थोपा गया था। मेड़ के निर्माण को लेकर पूर्व दुश्मनी के कारण। हमें इस तर्क का कोई आधार नहीं दिखता। पहली बात तो यह कि किसी भी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता नहीं चलता कि मौत पोस्टमार्टम होने से ठीक 24 घंटे पहले हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बस इतना कहती है कि मौत "पीएम जांच से 24 घंटे के भीतर" हुई थी। निस्संदेह, पोस्टमार्टम 11.7.1997 को सुबह 11.00 बजे/दोपहर 12 बजे किया गया था। दूसरे शब्दों में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृत्यु 10.7.1997 की दोपहर 11.00/12.00 बजे के बाद किसी भी समय हो सकती है। . पूरे शरीर में रिगोर मोर्टिस विकसित होने के समय को दर्शाने के लिए फोरेंसिक मेडिसिन पर पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में दिए गए तर्क का भी कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि मृतक की संरचना, वर्ष का मौसम, क्षेत्र का तापमान और वे परिस्थितियाँ जिनके तहत शरीर को संरक्षित किया गया है। रिकॉर्ड बताता है कि शव मुर्दाघर से लिया गया था। हमने देखा है कि डॉक्टर से किसी भी तरह की कोई जिरह नहीं की गई है, जिससे किसी भी भौतिक तथ्य का पता चल सके, जिस पर संभावित तर्क आधारित हो सकता था। यदि ये परिस्थितियाँ हैं, तो पूरे शरीर में कठोर मोर्टिस की उपस्थिति अपने आप में विद्वान वकील के इस तर्क की पुष्टि नहीं कर सकती है कि मृत्यु पिछली रात के दौरान हुई होगी। स्वीकार्य नेत्र साक्ष्य को ऐसे काल्पनिक आधारों पर खारिज नहीं किया जा सकता जिसके लिए कोई उचित आधार नहीं रखा गया था।

तब विद्वान वकील ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि मंगू खां के खेत में मेड़ का निर्माण घटना दिनांक से लगभग 10-15 दिन पूर्व कराया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि भले ही यह मान लिया जाए कि मृतक की भूमि पर अतिक्रमण करके बांध का निर्माण किया गया था, क्योंकि अभियुक्तों का कब्जा तय था और शिकायतकर्ता पक्ष जबरन बांध पर दोबारा कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे थे, निजी बचाव का अधिकार अभियुक्तों को उनकी संपत्ति और उनके व्यक्ति दोनों के संबंध में उपलब्ध था। विवाद पूरी तरह से निराधार और गलत है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी कोई दलील मुकदमे के दौरान नहीं उठाई गई, न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह के दौरान इसका सुझाव दिया गया। दूसरे, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शिकायतकर्ता पक्ष शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से आरोपी पक्ष के पास आ रहा था, क्योंकि वे पूरी तरह से निहत्थे थे। यह आरोपी पक्ष है जो लाठी, फारसी, टंचिया और कट्टा जैसे हथियारों से लैस नजर आया. इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत यह नहीं बताते हैं कि शिकायतकर्ता पक्ष के किसी भी

सदस्य ने कोई ऐसा कार्य किया था जिससे उचित आशंका पैदा हो सकती थी। अभियुक्तों के मन में उनके व्यक्ति या उनकी संपत्ति को खतरा है। हम विद्वान वकील के इस तर्क को भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं कि अभियुक्त को लगी चोटों से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं।'

विद्वान वकील ने अन्य आरोपों के अलावा यह भी तर्क दियापांच आरोपियों में से, जिन आरोपियों पर धारा 302 के तहत आरोप लगाए गए थे, उन्हें धारा 302 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था, लेकिन आईपीसी की धारा 302 आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। विद्वान वकील के अनुसार, चूंकि सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को धारा 302 के तहत आरोप से बरी कर दिया था, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए उन्हें आईपीसी की धारा 302 आर/डब्ल्यू धारा 34 के तहत दोषी ठहराना संभव नहीं था। विद्वान वकील की दलील के अनुसार, इससे अपीलकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यह कानून में एक गंभीर गलत दिशा है और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

उच्च न्यायालय ने, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की पुनः सराहना करने के बाद, निर्णय लिया देखें कि अभियोजन पक्ष आरोपी दीन मोहम्मद के खिलाफ धारा 148, 302/149 और 323/149 आईपीसी के तहत आरोप स्थापित करने में विफल रहा। और जमील खान उचित संदेह से परे। यही कारण था कि उन्हें बरी कर दिया गया। वर्तमान अपीलकर्ता संख्या 3 के संबंध में, उच्च न्यायालय का विचार था कि मौके पर अपराध करने के सामान्य इरादे का गठन उनके खिलाफ स्थापित किया गया था। मल्हू यादव और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। बनाम बिहार राज्य[3] उच्च न्यायालय ने माना कि हालांकि वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के तहत आरोप तय नहीं किया गया था, क्योंकि सबूतों से पता चलता है कि मौके पर अपराध करने का एक सामान्य इरादा था, धारा 302 आईपीसी के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया। आईपीसी की धारा 34 की सहायता से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि लसब और धंधड़ को उनके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों, अर्थात् खोपड़ी पर गंभीर चोटें पहुंचाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तीनों अपीलकर्ताओं का इस तरह की चोटें पहुंचाने का सामान्य इरादा था, यह उनके सुबह-सुबह मैदान में हथियारों के साथ इंतजार करने से स्पष्ट है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को

सही ठहराते हैं। जिस तरह से शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया गया और उनमें से दो को मौत के घाट उतार दिया गया, वह सबूतों से पता चलता है और इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष उचित हैं। हो सकता है, सबूतों से, उस व्यक्ति को इंगित करना संभव न हो जिसने प्रत्येक मृतक को घातक झटका दिया। शायद यही कारण है कि अपीलकर्ताओं को धारा 302 सरलीकरण के तहत चारपिनपॉइंट से बरी कर दिया गया था। लेकिन जब साक्ष्य यह इंगित करता है कि तीनों अभियुक्तों ने बार-बार लाठी, फ़ारसी और टंचिया से वार किया था, और किसी विशेष अभियुक्त की पहचान करना और उसे विशेष चोट का कारण बताना संभव नहीं है, तो अभियुक्त को इस आरोप के लिए दोषी ठहराने में कुछ भी अवैध नहीं होगा। आईपीसी की धारा 34 की सहायता से धारा 302 आई। धारा 34 के उद्देश्य के संबंध में, यह न्यायालय *बी.एम. दाना और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य" देखा गया:*

> "हम इस स्थिति को स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति विशेष हैया व्यक्तियों ने घातक प्रहार किये; लेकिन एक बार पता चला कि वह अपराधी है कार्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी है जैसे कि यह उसके द्वारा किया गया हो। इस अनुभाग का उद्देश्य ऐसे मामले को पूरा करना है जिसमें किसी पार्टी के अलग अलग सदस्यों के कृत्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है जो सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं या यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई थी। यह धारा जिस सिद्धांत को अपनाती है वह अपराध करने के सामान्य इरादे से किसी कार्रवाई में भाग लेना है; एक बार ऐसी भागीदारी स्थापित हो जाने पर, एस. 34 तुरंत आकर्षित हो जाता है।"

<u>वास्तव में, यह सटीक रूप से धारा 34 की भूमिका प्रतीत होती है, जैसा कि इस न्यायालय ने *हर्षदसिंह पहलवानसिंह ठाकोर* (सुप्रा) में संकेत दिया था। *कृष्णा अय्यर, जे. के अभिनंदनपूर्ण शब्दों में कानूनी प्रस्ताव है:*</u>

> "हम कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हैं: कि जब कई हाथों द्वारा कई चाकुओं से किया गया जानलेवा हमला घातक रूप से समाप्त हो जाता है, तो गंभीर लोगों को दूसरों से

अलग करना और उन लोगों को बचाने की कोशिश करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है जिनके वार घातक साबित नहीं हुए हैं। जब लोग खेलते हैं चाकुओं और जिंदगियों के साथ, वह परिस्थिति जब एक आदमी पर चाकू से वार किया जाता हैपीड़ित के व्यक्तित्व का कम या अधिक संवेदनशील हिस्सा हत्या का दोष तय करने के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब घातक इरादे से प्रेरित एक खूनी समूह संचयी रूप से अपना उद्देश्य पूरा करता है, तो संयुक्त मिलीभगत अपरिहार्य निष्कर्ष है। रचनात्मक दायित्व तय करने वाली आईपीसी की धारा 34 निष्कासन की ऐसी परिष्कृत दलील को निर्णायक रूप से शांत कर देती है। *(अमीर हुसैन बनाम यूपी राज्य* [5] देखें; *मैना सिंह बनाम बी राजस्थान राज्य* [6].) रचनात्मक आपराधिक दायित्व के लिए लॉर्ड सुमनेर का क्लासिक कानूनी शॉर्टहैंड, प्रतीक्षा करते हैं' एक फोर्टियोरी मामलों को गले लगाता है आम इरादे तुरंत बन गए, जिससे कई लोग आपराधिकता की ओर बढ़ गए, कुछ को मारा गया, कुछ को गायब कर दिया गया, कुछ ने शत्रुतापूर्ण सिर फोड़ दिए, कुछ ने खून की बूंदें गिरा दीं। अपराध-बोध भागीदारीपूर्ण उपस्थिति या संचालन के साथ इरादे के समुदाय के साथ जुड़ा होता है। दंड संहिता के स्पष्ट दंडात्मक उद्देश्य को निरस्त करने या ख़त्म करने के लिए किसी भी बेहतर न्यायिक बारीकियों को लागू नहीं किया जा सकता है।"

ऐसी स्थिति में जब एक को छोड़कर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है आरोप, धारा 34 की सहायता से धारा 302 के तहत अकेले आरोपी को भी दोषी ठहराना संभव है (इस संबंध में *सुख राम बनाम यूपी राज्य* [7] *और पीपल सिंह बनाम पंजाब राज्य* [8] भी देखें)

विद्वान वकील ने अंततः एक हताश अपील की कि यदि वे दोषी थे, तो अपीलकर्ताओं को केवल धारा 304 भाग I आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, न कि धारा 302 के तहत। हमें डर है, यह याचिका भी खुली नहीं है। स्थिति स्वतंत्र लड़ाई की नहीं थी। दूसरी ओर, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि इरादा उन लोगों पर घात लगाकर हमला करने और उन्हें मारने का था, जो बांध के अवैध

निर्माण का विरोध करने आ रहे थे। हमारे विचार में, स्थिति धारा 302 के अंतर्गत आती है न कि धारा 304 के अंतर्गत, जैसा कि आग्रह किया गया है।

हमें इन अपीलों में कोई तथ्य नहीं मिला, जिन्हें एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

एन.जे. अपील खारिज।

1 [1976) 4 एससीसी 640

2 . एआईआर [1988] एससी 863 पैरा 8।

3 सी(2002) 5 एससी सी 724

4 एआईआर (1960) एससी 289 पैरा 19

5. [1975] 4 एससी सी247।

6. [1976]2 एससी एससी21।

7. एआईआर (एल974) एससीसी323।

8. [2001]2 एससीसी 292.

चन्द्र कान्त शुक्ल की देख रेख में न. क दुवारा अनुवादित